करेंट अफेयर्स 5 सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल ऋण के लिए दिशानिर्देश जारी किए

- आरबीआई ने उपभोक्ताओं को डेटा गोपनीयता के उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों पर शुल्क लगाने और फिनटेक खिलाड़ियों द्वारा अनैतिक वसूली प्रथाओं से बचाने के लिए डिजिटल ऋण देने के मानदंडों को कड़ा किया।
- डिजिटल लेंडिंग में वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना, प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है। दिशानिर्देश सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि पर लागू होते हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- सभी ऋण संवितरण / पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता और आरई के बैंक खातों के बीच निष्पादित किए जाने हैं।
- बिना किसी जुर्माने के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने के लिए कूलिंग ऑफ / लुक-अप अवधि प्रदान की जाएगी।
- ऋणदाता नाम, ग्राहक का पता आदि जैसी जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं जो ऋण को संसाधित करने और वितरित करने और उसके पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक हैं।
- डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए) द्वारा उधारकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत नहीं की जा सकती है।
- आरई सभी डिजिटल उधार उत्पादों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप में अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्ता को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करेंगे।
- सीआईसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और अन्य के अनुसार क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सभी उधार की रिपोर्टिंग।

सम्बंधित खबर

- ऋण को और अधिक कुशल बनाने के लिए, उधारकर्ताओं की लागत कम करने और टर्नअराउंड समय के लिए, RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उधार के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
- पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ चलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की: एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट

इस क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट का उद्देश्य ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020–22 को पूरक बनाना है। इसमें दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को सारांशित करने वाला एक खंड शामिल है, जिसके बाद एक जीवन-चक्र के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा विकास, चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, 55.9% आबादी के पास अभी भी सामाजिक सुरक्षा के रूपों तक पहुंच नहीं है।
- पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पर खर्च जीडीपी का औसतन 7.5% रहा है, जिसमें आधे देश 2.6% या उससे कम खर्च कर रहे हैं।
- यह वैश्विक औसत 12.9% से काफी नीचे है।
- केवल 24.4% भारतीय, बांग्लादेश से कम (28.4%), किसी भी तरह के सामाजिक दायरे में हैं संरक्षण लाभ।
- भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति जीडीपी के पांच प्रतिशत से भी कम हैं।
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार में से तीन कर्मचारी बीमारी या काम में चोट लगने के दौरान सुरक्षित नहीं हैं।

- रिपोर्ट इस क्षेत्र के देशों से 'हाई-रोड' विकास पथ पर चलने का आग्रह करती है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्राथमिक भूमिका निभाती है।

ILO के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 में स्थापित, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। ILO के 187 सदस्य देश हैं: संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 186 और कुक आइलैंड्स। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, दुनिया भर में लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और 107 देशों में कुछ 3,381 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 1,698 तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं में काम करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022: उत्सव, थीम, महत्व और इतिहास

शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस देश के पहले उपराष्ट्रपति (1952-1962) के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967), एक विद्वान, दार्शनिक, भारत रत्न से सम्मानित, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। लेकिन शिक्षक दिवस पहली बार वर्ष 1962 में उनके 77वें जन्मदिन पर मनाया गया था। वह एक शिक्षक थे जो एक दार्शनिक, विद्वान और राजनीतिज्ञ बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के जीवन में शिक्षा के महत्व की दिशा में काम करने के लिए समर्पित कर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022: थीम

इस वर्ष के शिक्षक दिवस की थीम 'संकट में अग्रणी, भविष्य की फिर से कल्पना करना' है।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022: महत्व

शिक्षक दिवस एक ऐसा आयोजन है जिसके लिए छात्र और शिक्षक समान रूप से तत्पर रहते हैं। यह दिन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें अपने शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों को समझने का मौका देता है। इसी तरह, शिक्षक भी शिक्षक दिवस समारोह के लिए तत्पर हैं क्योंकि उनके प्रयासों को छात्रों और अन्य एजेंसियों द्वारा भी मान्यता और सम्मानित किया जाता है।

शिक्षक, राधाकृष्णन की तरह, देश के भविष्य के निर्माता हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके छात्र अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीने के लिए उचित ज्ञान और ज्ञान से लैस हों। शिक्षक दिवस हमारे समाज में उनकी भूमिका, उनकी दुर्दशा और उनके अधिकारों को उजागर करने में मदद करता है।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस: इतिहास

जब डॉ राधाकृष्णन ने 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला, तो उनके छात्रों ने उनसे 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति लेने के लिए संपर्क किया। इसके बजाय डॉ राधाकृष्णन ने उनसे समाज में शिक्षकों के योगदान को पहचानने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया।

तब से, 5 सितंबर को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्रों ने अपने सबसे प्रिय शिक्षकों के लिए प्रदर्शन, नृत्य और विस्तृत कार्यक्रमों की मेजबानी की।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022: सर्वपल्ली राधाकृष्णन

सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण परिवार में, मद्रास जिले के तिरुत्तानी में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी (बाद में आंध्र प्रदेश में 1960 तक, अब 1960 से तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में) में हुआ था। उनका जन्म सर्वपल्ली वीरस्वामी और सीता (सीताम्मा) से हुआ था। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सर्वपल्ली गांव का रहने वाला है।

पुरस्कार और सम्मान:

राधाकृष्णन को उनके जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 1931 में नाइटहुड, भारत रत्न, 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता शामिल है। वह संस्थापकों में से एक भी थे। हेल्पेज इंडिया, भारत में वंचित बुजुर्गों के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन।

शिक्षा:

राधाकृष्णन को उनके पूरे शैक्षणिक जीवन में छात्रवृत्तियों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वेल्लोर के वूरहिस कॉलेज में दाखिला लिया। अपने एफए (प्रथम कला) वर्ग के बाद, उन्होंने 16 साल की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज (मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध) में प्रवेश लिया। उन्होंने 1907 में वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उसी कॉलेज में अपने परास्नातक भी समाप्त किए।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन का करियर:

सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत भी रहे। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति।

जैसा कि भारत ने बचपन के टीकाकरण के साथ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और कोविड -19 टीकाकरण के साथ ऐसा करना जारी रखता है।

इसने अपनी अधिकांश आबादी तक पहुंचने के लिए समय और भूगोल की चुनौतियों को पार किया है, अंतिम-मील वितरण सुनिश्चित किया है, सरकारी स्तर पर एक निरंतर बड़े पैमाने पर संचालन को वित्तपोषित किया है, और लोगों के बीच विश्वास को विकसित और बनाए रखा है।

टीकाकरण क्या है?

किसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में मदद करने के लिए शरीर में टीका लगाने का कार्य टीकाकरण कहलाता है।

टीकाकरण सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक है, जो लोगों, विशेष रूप से बच्चों को भयानक टीके-रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाकर जीवन बचाता है।

महत्व:

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, टीकों ने पिछले 20 वर्षों में अकेले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 3.7 करोड़ मौतों को रोका है।

आर्थिक और सामाजिक लाभ:

यह अनुमान है कि 2021-30 से निचले मध्य-आय वाले देशों (LMIC) में 10 रोगजनकों के खिलाफ टीकाकरण में निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, निवेश पर प्रतिफल 52 रुपये होगा।

दो शताब्दियों पहले चेचक के टीके की खोज के बाद से, टीकों ने पोलियो, खसरा, टेटनस, काली खांसी, इन्फ्लूएंजा और हाल ही में, कोविड -19 जैसी बीमारियों के बोझ को प्रभावी ढंग से कम किया है।

टीकाकरण में भारत की उपलब्धियां क्या हैं?

पार्श्वभूमि:

भारत में सफल टीकाकरण का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें 18वीं शताब्दी में टीकाकरण के ऐतिहासिक विवरण हैं।

1977 में चेचक-मुक्त घोषित होने के बाद, भारत ने 1978 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI) शुरू किया और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन वैक्सीन (BCG), डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस (DPT), और ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन (OPV) टीके पेश किए। .

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (NHFS) डेटा:

नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के टीकाकरण की दर में पिछले दो दशकों में लगातार सुधार हुआ है और 'पूरी तरह से टीकाकरण' करने वाले बच्चों का अनुपात 76 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

पहल और उपलब्धियां:

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): भारत ने नवजात शिशुओं, शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में लगातार योगदान दिया है।

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी): इसके तहत, भारत राष्ट्रीय स्तर पर 11 बीमारियों और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी के खिलाफ टीके प्रदान करता है।

इसके अलावा, हर साल करीब 2.7 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करना।

सामूहिक टीकाकरण अभियान:

भारत ने एक महत्वाकांक्षी खसरा-रूबेला (MR) टीकाकरण अभियान शुरू किया और तीन वर्षों में 3 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया, जिससे बच्चों में दसियों हज़ार खसरे से होने वाली मौतों को रोका गया।

मिशन इंद्रधनुष:

2014 के बाद से, मिशन इंद्रधनुष जैसे कैच-अप राउंड के साथ टीकाकरण गतिविधियों को तेज किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में 90% का पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया जा सके।

बच्चों में रोटावायरल डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया को रोकने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (पीसीवी) को मेड-इन-इंडिया टीकों का उपयोग करके पेश किया गया और बढ़ाया गया।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) सिस्टम जैसी तकनीक का उपयोग जो पूरे वैक्सीन स्टॉक प्रबंधन, उनके लॉजिस्टिक्स और राष्ट्रीय स्तर से उप-जिले तक वैक्सीन भंडारण के सभी स्तरों पर तापमान ट्रैकिंग को डिजिटाइज़ करता है।

सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण ने 2014 में पूरी आबादी को पोलियो मुक्त होने के लिए सार्वजनिक स्वामित्व हासिल करने में मदद की।

विभिन्न टीकाकरण अभियानों के दौरान भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

कोविड -19 के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान: महामारी के दौरान, लॉकडाउन ने नियमित टीकाकरण सेवाओं में व्यवधान और स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद कर दिया।

टीकाकरण में हिचकिचाहट: एक अभूतपूर्व गति से टीकों को बाहर लाने के लिए वैश्विक सहयोग था, उन लोगों में एक 'इन्फोडेमिक-ईंधन' वैक्सीन झिझक भी देखी गई, जो पहले टीकों पर भरोसा करते थे।

टीकाकरण में भारत की सफलता के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य में क्षमता निर्माण: भारत ने अनुसंधान और विकास, और विनिर्माण क्षमता सहित अपने जैव चिकित्सा उद्यम का निर्माण किया है।

स्वदेशी रूप से उत्पादित रोटावायरस और पीसीवी टीके, और जिस गति से भारत स्वदेशी रूप से दो कोविड -19 टीकों का उत्पादन करने में सक्षम था, इन निवेशों पर प्रतिफल के उदाहरण हैं।

आधारभूत संरचना:

भारत ने कोल्ड चेन सिस्टम स्थापित करके और अंतिम छोर तक सेवाओं की स्थापना करने वाले श्रमिकों के सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्ग को विकसित और प्रशिक्षित करके अपने वितरण बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया।

व्यवहार संचार अभियान:

बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक और व्यवहारिक संचार अभियानों के माध्यम से मांग पक्ष में सुधार हुआ।

RACE IAS